भी कमी हुई है और सबस्टेंशियल कमी हुई है लेकिन समस्या विल की नहीं है, समस्या भूगोल की है। भूगोल हम नहीं बदल सकते । यहां तक कि राजस्थान में भी एक छोटा-सा एरिया है जहां पर तार लगाना संभव नहीं है। वहां पर जो सेंड डयून्स हैं वहां इतनी शिफ्टिंग है कि तार लगाओ तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए भूगोल की समस्या है। जम्मू-कश्मीर में तार लगाना संभव नहीं है। जिस एरिया में तार लगाना संभव है इंटरनेशनल बॉर्डर नियर जम्मू, उसके बारे में विचार किया जा रहा है और एक निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। विल की कोई कमी नहीं है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Mr. Chairman, Sir, from replies we came to know that arms have been provided to the citizens and the Village Defence Committees have been set up. What we want to know from the hon. Minister is, whether the Government has given any self-defence training to the inhabitants of the sensitive areas and if it is not given, whether the Government has any proposal or the Government would ensure that such a type of self-defence training would be given to the citizens inhabiting in the sensitive areas. Along with it, the military dictators of Pakistan should understand that, as far as the unity and integrity of his country is concerned, we will stand, cutting across party lines, as one man and protect this country. This meassage should go to Pakistan from this august House. I want to know whether you have got any proposal or whether you have taken any action to give self defence training to the citizens living in the sensitive areas bordering Pakistan.

SHRI L.K. ADVANI : When the Village Defence Committees are set up, the services of ex-servicemen are utilised, who are, in a way, already trained. Or, if some brief training is necessary, that has also been given. I fully appreciate what you have said that so far as terrorist and proxy war issues are concerned, the message to the whole world should be that the nation is united on this issue and there are no two opinions on this.

Poverty in Maharashtra

*362. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the poverty is going up day by day in rural areas of Maharashtra, particularly in backward and adivasi areas of the State ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) what action Government have taken or propose to take to solve this problem ?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SUNDAR LAL PATWA) : (a) to (c) As per the estimates of rural poverty (of the Planning Commission), the percentage of people living below the poverty line in Maharashtra has declined from 57.71 percent in 1973-74 to 37.93 percent in 1993-94, the year for which latest estimates are available. While poverty estimates have not, separately, been made by the Planning Commission for backward/adivasi areas, the poverty ratio for the Scheduled Tribes population in the rural areas of Maharashtra has been estimated at 50.58% for 1993-94.

The Ministry of Rural Development is implementing the following programmes for employment generation, poverty alleviation and to assist people below the poverty line in the rural areas of the country, including Maharashtra :—

(a) Employment Assurance Scheme

(b) Jawahar Gram Samridhi Yojana

(c) Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana

(d) Indira Awaas Yojana

(e) National Social Assistance Programme

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: सभापति महोदय, महाराष्ट्र में सहयाद्री और सतपुड़ा हिली एरिया हैं और विदर्भ में घने जंगल हैं। इनमें से दस से बारह जिले ऐसे हैं जहां ट्राइब्स रहते हैं और काफी मात्रा में , लगभग 80 प्रतिशत ट्राइब्स वहां रहते हैं। जो शेडयूल कास्ट लोग हैं वे पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। जो शेडयूल ट्राइब्स हैं उनकी सब-कास्ट 40 हैं और शेडयूल कास्ट हैं उनकी सब-कास्ट 35 हैं। ऐसी कुल मिलाकर 75 सब-कास्ट हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहां कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है।

मेरी जो मालूमात है उसके अनुसार हर वर्ष वर्षा ऋतु में कुपोषण के कारण, रोजगार के अभाव में, पीने का शुद्ध जल न मिलने के कारण, हेल्थ सेंटर न होने के कारण, ट्राइबल बालकों और महिलाओं की मृत्यु होती है। क्या इसके बारे में केन्द्र सरकार को मालूम है ? इस प्रकार से उनकी मृत्यु न हो, इसके लिए क्या कड़े उपाय किये जा रहे हैं ? माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार

योजना और इंदिरा आवास योजना आदि कई योजनाएं हैं। इतना होते हुए भी हर वर्ष वर्षा ऋतु में बालकों और महिलाओं की मृत्यु होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में कुछ ठोस उपाय करने का केन्द्र सरकार का क्या कोई मानस है ? दूसरी चीज़ यह है कि इतनी स्कीम्स होते हुए भी जो मृत्यु होती हैं, इसके बारे में कोई रिव्यु करने के लिए सरकार का मानस है क्या ?

श्री सुदर लाल पटवा : श्रीमन्, माननीय सदस्य के इस मत से मैं भी सहमत हूं कि वहां पर परिस्थिति अभी भी जिस प्रकार की होनी चाहिये, वैसी नहीं है। लोग कुपोषण में जीते हैं। जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, हम उस सारी परिस्थिति को बदलने के लिए जो सहायता यहां से करते हैं और जिन योजनाओं के अन्तर्गत करते हैं, उनका मैंने ज़िक्र किया है। राज्य सरकार को निरंतर इस बारे में अवगत कराते हैं क्योंकि राज्य का विषय होने के कारण हम क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। क्रियान्वयन राज्य सरकार को ही करना है। उन क्षेत्रों की स्थिति जो माननीय सदस्य ने कहा है, वैसी परिस्थिति है। उसको ध्यान में रखते हुए हम राज्य सरकार से निरंतर आग्रह करते हैं, सभी राज्य सरकारों से करते हैं कि इसमें क्रियान्वयन में सुधार लाया जाए।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार यह सब चीजें करती है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कई वर्षों तक मैं महाराष्ट्र विधान परिषद् का डिप्टी स्पीकर रहा हूं। अमरावती, धुरिया और नंदरबार जिलों में वर्षा ऋतु में हर वर्ष लगभग 100-125-150 मृत्यु हो जाती हैं लेकिन राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती है। तब केन्द्र सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस बारे में कुछ गाइडलांइस छोड़ दें लेकिन जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी हमेशा मृत्यु होती है केन्द्र सरकार की ओर से अपने अधिकारों का प्रयोग कर के कुछ विशेष रूप से क्रियान्वयन होगा क्या ?

श्री सुंदर लाल पटवा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र का अनुभव सुनाया, मैं भी कुछ समय मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुका हूं और मेरा भी अनुभव इस संबंध में वही है जो माननीय सदस्य का है। किन्तु केन्द्र सरकार की सीमा है। हम राज्य सरकारों को आगाह कर सकते हैं, राज्य सरकारों को आग्रह कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। परन्तु कुल मिला कर क्रियान्वयन का अधिकार राज्य सरकारों का है। उसका स्थान हम नहीं ले सकते हैं। इस मजबूरी को माननीय सदस्य समझें। माननीय सदस्य के विचार में अगर कोई और ऐसा विशेष उपाय है जिसे केन्द्र सरकार को अपनाना चाहिये और परिस्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य करना चाहिये तो मैं उनके सुझाव का स्वागत करूंगा।

SHRI R.S. GAVAI: Sir, I would like to know whether any review been done in respect of the schemes narrated by hon. Minister, as far as the tribal belt, particularly the Merghat belt, of Maharashtra is concerned. Hundreds of children and women are dying there because of malnutrition. So, the Central Government should come forward with a special assistance, instead of depending on the routine schemes of Government of India lemented by Maharashtra Government. Is there any scheme to give central assistance to the Government of Maharashtra ?

MR. CHAIRMAN: Now, the Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Cease-Fire by Militant Groups

*364. SHRI DRUPAD BORGOHAIN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) after the cease-fire with BLT, what is the position of other militant groups like NDF (B), BTF, Birsa Munda Force etc. in Bodoland areas ;

(b) whether they are preparing for such cease-fire; and

(c) what steps have been proposed or thought of by his Ministry with regard to identify questions in general and of Bodos in particular ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI) :

(a) and (b) There is no information available with the Government that other militant groups like NDFB, BTF, Birsa Munda Force, etc. in the Bodoland Autonomous Council Areas are preparing for suspension of operations, as agreed to with the BLT.

(c) The Assam Accord 1985 provides the framework for protecting, preserving and promoting the identity of the Assamese people in general. Similarly, the Bodo Accord 1993 provides the framework for socio-economic, educational, ethinic and cultural advancement of the Bodos.

Amount provided to Naxalite affected States

†*365. SHRI JHUMUL LAL BHENDIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government intend to get rid of the responsibility of naxalism by treating it as a State subject;

†Original notice of the question was received in Hindi.